

लोकतंत्र और नैतिकता

यह विंडब्ना ही है कि सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते सरकार गाने-गिराने का जो खेल हाल के दशकों में राज्यों में नजर आया, उसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठे हैं। कहीं इस पद की गरिमा के विपरीत राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर व्यवहार करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि यह प्रवृत्ति हाल में ही उभरी हो, आजादी के कुछ दशकों के बाद ही यह खेल निरंतर जारी रहा है। राज्य में विपक्षी दलों की सरकारी गिराने के लिये इस पद का दुरुपयोग कांग्रेस से लेकर राजग सरकारों दौर में होता रहा है। इस संकट को महसूस करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र प्रकरण में तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कड़ी टिप्पणी की कि सत्तारूढ़ पार्टी में असंतोष की स्थिति में यपाल का बहुमत साबित करने को कहना अनुचित है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल में यदि मतभेद होने पर बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता हो तो निर्वाचित सरकार के अस्तित्व पर संकट पैदा हो सकता है। यानी में राज्यपाल की भूमिका हस्तक्षेप करने वाली नहीं होनी चाहिए। असल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. वाईष्य चंद्रचूड़ की अध्यक्षता ली पांच सदस्यीय संविधान पोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि यह किया जाता है तो यह लोकतंत्र का प्रहसन ही होगा। उल्लेखनीय है खंडपीठ ने यह टिप्पणी बीते साल अविभाजित शिवसेना में एकनाथ दे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद राज्य में पैदा राजनीतिक संकट के बत की। तब भी राज्यपाल की भूमिका को लेकर विपक्ष ने कई साल खड़े किये थे। दरअसल, कोर्ट ने इस संकट के बाबत दायर चिकिपार सनवाई के दौरान ही यह तल्ख टिप्पणी की। उल्लेखनीय है चिकिपार पर सनवाई के दौरान ही यह तल्ख टिप्पणी की। उल्लेखनीय है

कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा व शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कालांतर सत्ता में बंटवारे को लेकर दोनों दल अलग गये थे और कम विधायकों वाली शिवसेना ने कुछ विपक्षी दलों समर्थन से सरकार बना ली थी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि राज्य में शिवसेना की सरकार बनने के बाद भाजपा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से शिवसेना सरकार पर हमलावर रही है। इस काम में जहां तम विवादों में सरकारी एजेंसियों के इस्टेमाल के आरोप लगे, वहीं राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते रहे। केंद्र की सत्ता में होने का लाभ राजभाजपा को मिला। राजग के सबसे पुराने सहयोगियों में रहे शिवसेना भाजपा में कटुता इस हद तक जा पहुंची कि बात सरकार को गिराने तक में परोक्ष भूमिका तक पहुंच गई। यह राजनीतिक विद्रूपता ही है कि किसी पार्टी के बैनर तले चुनकर आये जनप्रतिनिधि सत्ता व असुविधाओं के प्रलोभन में पाला बदलकर मूल दल के विरोधियों साथ बगलगीर हो जाते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार भाजपा के समर्थन से ही अस्तित्व में बहुई है। सही मायनों में शीर्ष अदालत ने इन्हीं राजनीतिक विद्रूपता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि राज्यपाल द्वारा किसी राजनीतिक दल में असंतोष के चलते बहुमत साबित करने को कहना अपरोक्ष रूप से सरकार को अस्थिर करना ही है। कुल मिलाकर कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका के नैतिक पक्ष को उजागर करने के साथ ही इस पद व गरिमा को बनाये रखने का संदेश दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफसे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता ने दलील दी कि ई वाजिब कारण मौजूद थे, जिसके चलते राज्यपाल ने उद्धव सरकार को सदन में बहुमत साबित करने को कहा था। इसमें शिवसेना के 3 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी शामिल था। जिसमें तत्कालीन उद्धव ठाकरे नीत सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही गई थी।

संविधान बचाने की चिंता

22 मार्च से चौत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है आर हमशा का तरह दश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। भारत में बरसों से ऐसा ही आया है, और धीरे-धीरे पिल्मों, टीवी धारावाहिकों और भक्ति से जूनलों के कारण पूजा-पाठ का प्रसार कुछ अधिक हो गया है। उन्हें कुछ वक्त में राजनीति का चरित्र भी बदला है तो अब राजनेताओं पूजा-पाठ, व्रत, हवन भी सार्वजनिक कार्यक्रम बन गए हैं। देश के मंके और राजनीतिक चरित्र में बदलाव के इस सिलसिले को आगे लेते हुए अब उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को चौत्र त्रितीयों और रामनवमी के दौरान मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम योजित करने को कहा है। योगी सरकार इन कार्यक्रमों में प्रदर्शन ने के लिए चुने गए कलाकारों को मानदेय के रूप में भुगतान करने लिए प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपये भी उपलब्ध कराएगा। राज्य के क्षुति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने 10 मार्च को जारी 5 आदेश में कहा है कि चौत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान नवरात्रम् ऊर्जा को खत्म करने के लिए देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की रात्रा की जाती है, इसलिए इस अवधि में धार्मिक और सांस्कृतिक विधियों का आयोजन प्रस्तावित है। यह आदेश सभी जिला मणिस्ट्रेटों और संभागीय आयुक्तों को भेजा गया है। प्रत में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष, तहसील और जिले में आयोजन प्रस्तावित है। यह सुझाव भी दिया गया है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा शती और अखंड रामायण का पाठ कराया जाए। आदेश के अनुसार, योजकों से संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर तस्वीरें अपलोड करने अपेक्षा की जाती है। आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों को मन्त्रित किया जाए और बड़ी जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। उत्तरप्रदेश कार के इस फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या यह राज्य विधान के अनुसार चलेगा या धर्म के आधार पर। और धर्म का ललब यहां हिंदू धर्म से है, क्योंकि बाकी धर्मवर्लंबियों को हिंदुत्व के कारण विधर्मी कहते हैं। कर्णाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब नने के सवाल पर छात्राओं के साल के साल बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का तकाजा दिया जा रहा है कि शैक्षणिक परिसरों में भेंटक पोशाकों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हिंदुस्तान के कई लोगों में देवी सरस्वती की मूर्ति बनी हुई है। प्रार्थना के बाद बच्चे ग्रन्ति मंत्र का पाठ करते हैं।

अमेरिका में बंदूक

ललित गर्ग

अमेरिका में आए दिन ऐसी खबरें आती रहीं कि किसी सिरपिरे ने अपनी बंदूक से कहीं स्कूल में तो कभी बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें नाहक ही लोग मारे गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण वहां आम लोगों के लिए हर तरह के बंदूकों की सहज उपलब्धता है। हिंसा की बोली बोलने वाला, हिंसा की जमीन में खाद एवं पानी देने वाला, दुनिया में हथियारों की आंधी लाने वाला अमेरिका जब खुद हिंसा का शिकार होने लगा तो उसकी नींद टूटी है। अमेरिका की आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी मुश्किल यहीं रही है कि यहां हिंसा इतनी सहज बन गयी है कि हर बात का जवाब सिर्फ हिंसा की भाषा में ही दिया जाने लगा। वहां हिंसा का परिवेश दबाना मनना दो गया है कि वहां रही

बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूल द्वारा आयोजित हवनों में शामिल नहीं हैं। शारदीय नवात्र के दौरान देश के कई शहरों में रात-रात भर बा चलता है। अब तो स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी गरबा करते हाथियों को देखा जा सकता है। अभी होती बीती है और इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें दूसरे धर्म के लोगों पर, खासकर महिलाओं पर जबरदस्ती रंग फेंका जा रहा है। केन इन सब को देखकर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। क्योंकि लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि भारत हिंदुओं देश है और यहां हिंदुओं को पूरा हक है कि वे चाहे जैसे अपनी ऐरंग भावनाओं को प्रकट करें, धर्म के नाम पर जो तमाशा चाहें, वो उड़ा कर लें। कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मॉल, अस्पताल या नन्ही ट्रेन में कोई शांति से एक और नमाज पढ़े, तो लोगों को हिंदू धर्म पर भारत नजर आने लगता है। वे तब सर्विधान की आड़ में धर्मनिरपेक्षता की जानकारी करने लगते हैं। यही कुतुक क्रिसमस या न्यू ईयर के उत्सवों पर भी जाता है, क्योंकि बाजार की चकाचाँध इन त्योहारों पर अधिक होती और इन्हें मान कर जनता का एक तबका खुद को आधुनिक समझने लगता है। किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार मनाने में कोई आपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन यह धार्मिक उदारता सभी धर्मों के त्योहार पर देखने मिलेगी, यह एक कड़वी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश सरकार किस हक से दाताओं के पैसे को नवात्र मनाने के लिए खर्च कर सकती है, यह लाल किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे ले कंवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में भी जनता का ही धन आ और जनता चुप रही। त्योहार पर मुफ्त सिलेंडर देने का बाद करने ले त्योहार के ऐन पहले सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं, जनता तब भी चुप रहती है। क्योंकि उसे भव्य राम मर्दिद बनाने देखना है। इस मर्दिर में आराध्य के दर्शन और पूजापाठ की भारी रकम उसे शायद चुकाना; क्योंकि अब भगवान तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया भी महंगी हो गई लेकिन धर्म बचने के लिए जनता यह सारे कष्ट सह लेगी।

अमेरिका, रूस और चीन के आपसी टकराव से वैश्विक शांति को खतरा

संजीव ठाकुर

अमेरिका ने चीन और ताइवान के संबंधों को लेकर ताइवान का खुलकर साथ देने की बात कही जिससे चीन ने आक्रामक होकर इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कहां है और कहा है कि यदि हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा तो बर्दाशत नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर रूस अब बहुत संवेदनशील और आक्रामक हो गया हैस यूक्रेन से रूस ने अब निर्णायक पारी खेलने का मन बना लिया हैस इस तरह अमेरिका यूक्रेन तथा ताइवान को साथ देने के चक्रम में रूस और चीन से सीधी-सीधा टकराने के मूड में आ गया है। यह अलग मुद्दा है की सांडो की लडाई में खेतों की मेढ़ बरबाद जरूर होती हैं। इन तीनों महा बलियों की लडाई में अन्य पड़ोसी देशों की शांती भंग हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से यूक्रेन का साथ देने की कटिबद्ध है, एवं पूर्वी यूरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस पर दबाव डालने के लिए सैन्य बल भेजने की बात कही हैस अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस वार्ता के हवाले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस ने सीमा के आसपास बड़ी संख्या में सैन्य जमवाड़ कर चुका है, एवं रूसी बलों को तैनात किया हैस जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अन्य सैन्य बल तथा बातचीत के जरिए का विकल्प भी मौजूद हैस वर्तमान की परिस्थितियों में यूक्रेन की सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा

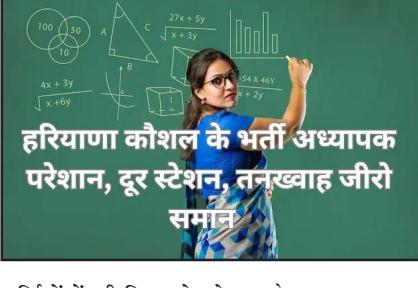


कि रूस फवरी या मार्च के प्रथम सप्ताह तक बड़ा हमला कर सकता है स व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता एमिली होर्न ने बताया की अमेरिकी राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि रूस फवरी में यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लाइड ऑस्टिन ने कहा कि हमारा मानना है कि यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर एपुतिन का यह अंतिम फैसला नहीं है, जबकि उनके पास कई विकल्प खुले हुए हैं। यूक्रेन पर हमला करने की निसंदेह रूस के पास संपूर्ण क्षमताएं हैं। अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति रक्षा मंत्री ने पुतिन से यूक्रेन पर तनाव कम करने की अपील भी की है। रूस ने कहा है कि वार्ता के द्वारा भी खुले हुए यदि यूक्रेन अपनी हठधर्मिता से पीछे हटता है तो रूस वार्ता के माध्यम से एक मध्य मार्ग के बारे में विचार कर सकता है। पर यूक्रेन अपनी तीनों शर्तों पर अड़ा हुआ वह क्रीमिया महाद्वीप को वापस लेना चाहता है और नाटो की सदस्यता भी चाहता है, रूस द्वारा पाइप लाइन बिछाकर उसकी आर्थिक स्थिति

कमजोर करना चाहता हैं जिसे वह कभी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य बल को मदद करने को तैयार है। रूस के पास अब सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन पर चढ़ाई करने के अलावा कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की यह आशंका कि रूस यूक्रेन पर फरवरी एवं मार्च के प्रथम सप्ताह में बड़ा हमला कर सकता है निर्मूल नहीं है। अमेरिका ने निर्णय लिया है कि वह पूर्वी यूरोप के सीमा पर एक बड़ा सैन्य बल रूस को टक्कर देने के लिए भेजेगा संभवत यह रूस पर दबाव डालने के लिए एक कूटनीतिक घोषणा एवं चाल हो सकती है। कुल मिलाकर यूक्रेन की सीमा पर जिस तरह से सैनिकों का जमवाड़ा इकट्ठा हो गया है, उससे जंग की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफके आर्मी जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन के निकट तैनात रूसी सेना गंभीर तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर उसने जपीन, वायु, जल क्षेत्र में बलों की तैनाती कर दी है, साथ ही रूस के पास साइबर तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमताएं भी हैं। इसके अलावा उसके पास विशेष अभियान दल भी हैं। मिले के अनुसार यह अत्यंत चिंताजनक एवं विचारणीय प्रश्न है कि इसके पूर्व रूस की इतनी लंबी चौड़ी सेना की तैनाती कभी भी यूक्रेन की सीमा पर नहीं देखी गई है। इसका मतलब सीधा और साफ़ है कि रूस युद्ध के प्रति एकदम गंभीर है एवं यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता है। पर इसे वैज्ञानिक विश्लेषक अधिनायकवाद इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला बताते हैं, जिससे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ावा मिल सकता है, और विश्व युद्ध होता है तो बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध होने की पूरी संभावना है। मिले ने पुतिन से संघर्ष के बदले कूटनीतिक मार्ग अपनाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास एक लाख से ज्यादा सैनिक तथा जमीन से जमीन मारक क्षमता वाले टैंक तथा लड़ाकू हवाई जहाज तैनात करके रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन जैसे छोटे देश के पास अमेरिका ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देश और नाटो देश के सदस्यों से सैन्य दल लेने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं बचा है। यह तो तय है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए कटिबद्ध है पर बदली हुई परिस्थितियों में यूक्रेन का साथ देने के लिए कहीं अमेरिका अलग-अलग ना पड़ जाए, इसके अलावा उसने चीन को इस मामले में दखल नहीं देने चेतावनी भी दी है। फिलहाल चीन ताइवान मामले में अमेरिका के सीधा सामग्रे है। वर्तोंकि अमेरिका ताइवान को भी मदद करने का वादा कर चुका है, ऐसे में अमेरिका को कई तरफ अपनी सेनाएं भेजने का काम करना होगा। कुल मिलाकर यूक्रेन, रूस, चीन, ताइवान को लेकर वैश्विक स्तर पर अर्शांति का माहोल बना हुआ है। कूटनीतिक बातचीत कर इसका हल निकाल कर वैश्विक शांति का संदेश देना चाहिए।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਮਹੀਨੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਰੀ ਜੀਰੋ ਸਨਾਨ

प्रियका सारम



तुखिया न रहा। कि हमन पापों का जावर पर राय के गरीब युवाओं को नौकरी देकर एक अनुपम कार्य किया है। मगर इन अध्यापकों को भर्ती हुए आज चार से पांच महीने होने को है। मगर अभी तक इनके खाते में छ भी नहीं आया। वेतन की बात तो दूर इन नए अध्यापकों को घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्कूल स्टेशन दिए गए। कहीं-कहीं तो ऐसे स्कूल स्टेशन दिए गए। जहां पहुंचना जंगल में रास्ता खोजने से कम नहीं है। यातायात की कमी के चलते अध्यापकों को स्कूल तक पहुंचने में बड़ी मशक्त करनी पड़ती है। मेरे इस प्रश्न के जवाब में सरकार के नुमाइंदे यह भी कहेंगे कि क्यों ये अध्यापक वहाँ रहकर अपनी डियूटी क्यों नहीं करते तो जनाब इसका सीधा सा उत्तर है कि 15000 से 20000 की नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवार सहित इस महांगाई के जमाने में कैसे किराए के घर पर रहेगा और अपने दैनिक कार्यों को इस छोटी सी तनखाह से पूरा कर पाएगा। यह काफी सोचनीय विषय है और ये समस्या महिला अध्यापकों

क रहा है तो सा युग कढ़ा जाता है। प्राचीन मानविकी का अपने अलावा अपने बच्चों के साथ-साथ सास-समूह सहित पूरे परिवार की देखभाल भी करनी होती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर स्टेशन देने के कारण ये महिला अध्यापिकाएं रोजाना सफर नहीं कर सकती और न ही कम तनखाह के चलते अपनी ड्यूटी स्टेशन पर अपना नया घर बसा सकती है और आज के दिन तो घर बसे भी कैसे? पिछले तीन महीनों की नौकरी में खाते में 1 भी नहीं आया है। इतने दिन अपनी जेब से या घरवालों से उधार ही लेकर काम चल रहा है यही नहीं सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक करने में महिलाओं को काफ़ी शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है जैसे जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनको दोहरे कर्तव्य निभाने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो उनको खुद को देखभाल की जरूरत है तो दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी की चिंता है। ऐसे में हरियाणा कौशल राज्य के युवाओं के लिए नौकरी के मामले में गले की फंस बन गया है। एक तरफ जहां कौशल में नाम आने पर युवाओं को नौकरी की खुशी होती है तो दूसरी तरफ ज्ञानिंग के पहले दिन भविष्य का गम सताने लग जाता है। राज्य के मुखिया मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की विधानसभा में कह चुके हैं कि कौशल के तहत भर्ती किए गए कर्मचारी कच्चे हैं और जब इन पदों पर नियमित कर्मचारी आ जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसे में युवा नौकरी करें तो कैसे करें? बेरोजगारी का आलम यह है कि इनको पेट के लिए यह नौकरी करनी पड़ रही है। राज्य के शिक्षित युवा आज दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही। अगर उठाती है तो कौशल के नाम पर उछू बनाती है। अगर हम काशल के तहत नामा लिए गए अध्यापिका के स्थानान्तरण के मामले को सोचें तो स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर हरियाणा कौशल के महाप्रबंधक तक को इस बात का पता नहीं है कि इस मामले में आखिरी क्या होगा? ऐसे में स्थानान्तरण की अर्जी लेकर राज्य के हजारों अध्यापक किस दरवाजे पर जाएँ? महिला अध्यापिकों की अति संवेदनशील समस्या को अब कौन सुने? समस्या को कैसे सुलझाया जाए? यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को इस मामले को प्राथमिक तौर पर देखना चाहिए, न ए अध्यापिकों खासकर महिला अध्यापिकों को प्राथमिकता के आधार पर नजदीकी स्टेशन पर तैनात किया जाये और उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाए, ताकि मध्यांतर में उनको बेवजह मानसिक दबाव का सामना खासकर स्टेशन को लेकर न करना पड़े और यही नहीं हरियाणा सरकार को कौशल के तहत भर्ती किए गए अध्यापिकों के वेतन बरें में ठोस कदम उठाने होंगे। अभी तक इनके खाते में 1 भी आखिरी क्यों नहीं पहुंचा? इनके मासिक वेतन की तारीख फिर्स की जाए और समय पर तनखाह डाली जाए। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग कौशल कर्मचारियों अध्यापिकों की समस्याओं को नियमित कर्मचारियों की समस्याओं की तरह ही देखें और इन पर तुरंत संज्ञान लें। तभी इन अध्यापिकों के अलावा हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का भला होगा और यह नए भर्ती किए योग्य उच्च शिक्षित अध्यापक अपने मानसिक दबाव को एक तरफ खट्टर कर बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना शत प्रतिशत योगदान दे सकेंगे।

अमेरिका में बंदूक सरकृत ने बड़ा सामाजिक संकट खड़ा कर दिया है

आए दिन ऐसी

कि किसी सिरपिरे ने अपनी बन्दूक से कहीं स्कूल में तो कभी बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें नाहक ही लोग मारे गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण वहां आम लोगों के लिए हर तरह के बंदूकों की सहज उपलब्धता है। हिंसा की बोली बोलने वाला, हिंसा की जमीन में खाद एवं पानी देने वाला, दुनिया में हथियारों की आंधी लाने वाला अमेरिका जब खुद हिंसा का शिकार होने लगा तो उसकी नींद टूटी है। अमेरिका की आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी मुश्किल यही रही है कि यहां हिंसा इतनी सहज बन गयी है कि हर बात का जवाब सिर्फ हिंसा की भाषा में ही दिया जाने लगा। वहां हिंसा का परिवेश इतना मजबूत हो गया है कि वहां की बन्दूक-संस्कृति से वहां के लोग अपने ही घर में बहुत असुरक्षित हो गए थे। लंबे समय से बंदूकों की सहज उपलब्धता का खामियाजा उठाने के बाद वहां के लोगों ने अपने स्तर पर इसके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को हथियारों के दुरुपयोग पर अंकुश से संबंधित कार्यकारी आदेश पर किये हस्ताक्षर करने को विवश होना पड़ा है। पिछले साल जून में भारी तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतर कर बंदूकों की खरीद-बिक्री से संबंधित कानून को बदलने की मांग की। जरूरत इस बात की है कि इस समस्या के पीड़ितों को राहत देने के साथ-साथ बंदूकों के खरीदार से लेकर इसके निर्माताओं और बेचने वालों पर भी सख्त कानून के दायरे में लाया जाए। अमेरिका की ही तरह पंजाब में पनप रही बन्दूक-संस्कृति को भी नियंत्रित किया जाना जरूरी है। अमेरिका में आए दिन ऐसी खबरें आती रहीं कि किसी सिरपिरे ने अपनी बन्दूक से कहीं स्कूल में तो कभी बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें नाहक ही लोग मारे गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण वहां आम लोगों के लिए हर तरह के बंदूकों की सहज उपलब्धता है और इन बन्दूकों का उपयोग मामूली बातों और उन्मादग्रस्त होने पर अंधाधुंध गोलीबारी में होता रहा है, जो गहरी चिन्ता का



सिराफर व्यक्ति को सनक से किसी बड़ी अनहोनी का अन्देशा हमेशा वहां बना रहता है, वहां की आस्थाएं एवं निष्ठाएं इतनी जख्मी हो गयीं कि विश्वास जैसा सुरक्षा-कवच मनुष्य-मनुष्य के बीच रहा ही नहीं। साफ चेहरों के भीतर कौन कितना बदसूरत एवं उन्मादी मन समेटे है, कहना कठिन है। अमेरिका की हथियारों की होड़ एवं तकनीकीकरण की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। अब तो दुनिया के साथ-साथ अमेरिका स्वयं ही इन हथियारों एवं हिंसक मानसिकता का शिकार है। अमेरिका दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने एवं अपने सांस्कृति को उसने दुनिया में फैलाया है, उससे पूरी मानवता कराह रही है, पीड़ित है। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था (न्यू वर्ल्ड आर्डर) की बात की है, खुलेपन की बात की है लगता है विश्वमानव का दम घुट रहा है और घुटन से बाहर आना चाहता है। विडम्बना देखिये कि अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित देश है लेकिन उसके नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और भयभीत नागरिक हैं। वहां की जेलों में आज जितने कैदी हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं। ऐसे कई वाकये हो चुके हैं कि किसी रेस्तरां, होटल या फिर जमावड़े पर अचानक किसी सिरफिरे ने गोलीबारी शुरू कर दी और बड़ी तादाद में लोग मारे गए। 2014 में अमेरिका में हत्या के कुल दर्ज करीब सवा चौदह हजार मामलों में अड्सठ फैसल में बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। खुद सरकार की ओर से कराए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया था कि अमेरिका में सत्रह साल से कम उम्र के

होत है। अमेरिका प्रशासन का बदूक संस्कृति ही नहीं बल्कि हथियार संस्कृति पर भी अंकुश लगाना होगा, अब तो दुनिया को जीने लायक बनाने में उसे अपनी मानसिकता को बदलना होगा। कोई घातक हथियार साथ में होने के बाद मामूली बातों पर होने वाले झगड़े या फिर बेवजह ही किसी के उन्माद से ग्रस्त हो जाने पर कैसे नतीजे सामने आ सकते हैं, अमेरिका ने उसे करीब से देखा है, जहां हर साल सैकड़ों लोग इसकी बजह से मारे जाते हैं। किसी भी संवेदनशील समाज को इस स्थिति को एक गंभीर समस्या के रूप में देखना-समझना चाहिए। यह बेवजह नहीं है कि जिस अमेरिका में ज्यादातर परिवारों के पास अलग-अलग तरह की बंदूकें रही हैं, वहां अब इस हथियार की संस्कृति के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। यह आवाज उठना बहुत जरूरी था, देर आये दुरुस्त आये की कहावत के अनुसार अमेरिका की आंख खुली है तो अमेरिका के साथ दुनिया को एक शांति एवं अहिंसा का सन्देश जायेगा। निश्चित ही अमेरिका में हिंसा की इस संस्कृति पर नियंत्रण नितान्त जरूरी था। क्योंकि अमेरिका आज दुनिया में अपराध का सबसे बड़ा अड्डा है और हिंसा की जो संस्कृति उसने दुनिया में फैलाई, आज वह स्वयं उसका शिकार है। जाहिर है कि वहां होने वाली गोलीबारी की घटनाएं सैकड़ों लोगों के प्राण लेती रही हैं जो इस्लामी आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती थीं तो फिर यह क्या थी? यह ऐसा सवाल है, जो अमेरिकी सभ्यता को बेनकाब कर देता है। क्या यह अमेरिका की भौतिकतावादी एवं हिंसक संस्कृति की निष्पत्ति है? पीड़ितों के मानसिक आघात और अन्य मुश्किलों को समझते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को बंदूक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में सार्थक पहल की है। इसके तहत बंदूक की बिक्री के दौरान की जाने वाली ‘पृष्ठभूमि जांच’ को बेहतर बनाया जाएगा। इसके जरिए बाइडेन ने मंत्रिमंडल को बंदूक हिंसा से जूझ रहे समुदायों के समर्थन के लिए एक बेहतर सरकारी तत्र बनाने का निर्देश दिया है। यह छिपा नहीं है कि बिना किसी बजह के की गई गोलीबारी में किसी प्रियजन को गंवाने वालों को किस तरह के मानसिक आघात और

संस्कृत सकल शास्त्रों एवं संस्कृतियों का मूल है : प्रो. प्रयाग नारायण निर्णय लेने की शक्ति देना ही महिला सशक्तिकरण है : डॉ. रथिम

संचादन

प्रयागराज। इविष्ट में राष्ट्रीय सेवा योजना के छठवें दिन इकाई-20 का शुभारंभ मंगानाथ ज्ञा विस्तार भवन में प्रो. प्रयाग नारायण मिश्र, डॉ. विशाल विजय, डॉ. रशम यादव, डॉ. विकास शर्मा एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राधवेन्द्र मिश्र के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में महेश कुमार शुक्ल, शिवेंद्र मिश्र एवं अरुण तिवारी ने वैदिक मंगानाथण, स्वरित वाचन एवं स्मारक गीत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि अनुष्ठान प्रो. प्रयाग नारायण मिश्र इवि.वि. ने नारी शक्ति एवं नारी शिक्षा पर वक्तव्य देने हुए कहा कि निर्णय लेने की शक्ति देना ही महिला सशक्तिकरण है अतिथि वका. डॉ.विकास शर्मा इवि.वि. ने स्वामी विवेकानंद एवं युवा पर वक्तव्य देने हुए कहा कि अगर संपूर्ण भारत की समझाना है तो स्वामी विवेकानंद को पराएं जैसे वायु सकल भूत की जीवनदायिनी बनकर प्रेरित करती है उसी प्रकार युवा अपने सद् आवरण एवं लग्न मणिकांचन संसांग अद्भुत है। प्रिय

उन्होंने स्वयंसेवकों में सेवा भाव निहरित करता है। अंत में कार्यक्रम का सफलता पूर्वक संचालन एवं आभार ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राधवेन्द्र मिश्र ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिभुतिक बनने के होड़ में भारतीय केल पाण्डाल्य संस्कृत का अंधाकरण करते जा रहे हैं और वे वैदेव पद्धति एवं ऋषि-ऋषिक परम्परा का अनुकरण करें सकर्वैनम् अधिकारी डॉ. राधवेन्द्र मिश्र के दिवं निर्देश में आज पु: पृथ्वीविद्यालय के संस्कृत हाल के पास में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रस अवसर पर महेश शुक्ल, कृष्ण विहारी दुर्ग, हरिहरोग, तिवारी, अशुल, अक्तिक पाल, विकास गुप्ता, शिवेंद्र, अरुण तिवारी, सूरज, विनय कुमार, अंकित सोनकर, अनुराग शर्मा, अभिनव शुक्ल, अंकुर जायसवाल, अनुराग मिश्र, संकेंद्र, अशु पांडे आदि

उन्होंने स्वयंसेवकों को शिक्षा एवं अरुण तिवारी ने वैदिक मंगानाथण, स्वरित वाचन एवं स्मारक गीत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि अनुष्ठान प्रो. प्रयाग नारायण मिश्र इवि.वि. ने नारी शक्ति एवं नारी शिक्षा पर वक्तव्य देने हुए कहा कि निर्णय लेने की शक्ति देना ही महिला सशक्तिकरण है अतिथि वका. डॉ.विकास शर्मा इवि.वि. ने स्वामी विवेकानंद एवं युवा पर वक्तव्य देने हुए कहा कि अगर संपूर्ण भारत की समझाना है तो स्वामी विवेकानंद को पराएं जैसे वायु सकल भूत की जीवनदायिनी बनकर प्रेरित करती है उसी प्रकार युवा अपने सद् आवरण एवं लग्न मणिकांचन संसांग अद्भुत है। प्रिय

महाविद्यालय के कैंपस बाजार में हुई जमकर खरीददारी

संचादन

प्रयागराज। हेमवती नन्दन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय की स्किल डेवलपमेंट कमेटी ने भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत महाविद्यालय और महात्मा गांधी नेशनल कार्डिसिल आफ रूल डेवलपमेंट के तत्वावधान में सोमवार को फैसला बाजार जो आयोजन किया। जिसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपने प्रोडेक्ट के स्टॉल प्राइवेट ट्रैनिंग के साथ प्रारंभिक अध्यक्षता और प्रकाशन के लिए उत्पादन की विकास योजना की आयोजन किया। जिसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपने प्रोडेक्ट के स्टॉल प्राइवेट ट्रैनिंग के साथ प्रारंभिक अध्यक्षता और प्रकाशन के लिए उत्पादन की विकास योजना की आयोजन किया।



जमकर खरीदारी की इसमें फैशन ज्वेलरी, हस्त निर्मित सामग्री, मोमबत्ती, आर्ट वर्क, फैल्डर, चाकेट, हस्त निर्मित वस्त्र, हर्बल साबुन, विविध मिलेट के स्टॉल छात्र छात्राओं ने लगाये इस कार्यक्रम में खाने पोंछने की विभिन्न सामग्रियों के स्टॉल भी लगाये गये। उक्त जानकारी

पॉपुलरिटी के मामले में एमसी स्टेन को भी दे डाली मात, रैपर को मिली बड़ी हार



बिंग बॉस सीजन 16 विनर और रैपर एमसी स्टेन लगातार सफलता की सीधियां चढ़ रहे हैं शो में पहले उनकी जीत फिर उसके बाद अप-टू-डेट उनके कसर्ट्स उनकी सफलता में चार-चाँद लगा रहे हैं। बिंग बॉस जैसे शो ने उनकी लोकप्रियता में मनो लाखों सितारे ही जोड़ दिए हैं। वह लगातार एक सिंडी से दुसरी सिंडी जाकर अपने शोज कर रहे हैं और दुनिया में अपने प्रशंसन बाहर कायम कर रहे हैं। बिंग बॉस से उनके बाद एमसी स्टेन ने बॉलीवुड के मशहूर गायक ए आर रहमान को भी लोकप्रियता के मामले में पीछे पछाड़ दिया था। हालांकि, अब उनकी खुद की लोकप्रियता पर काफ़ी रुकावा देखा गया है। हाल ही में एक नई लिस्ट में बाहर कायम कर रही है, जिसमें बाहरी महीने लोगों ने सोशल मीडिया पर एमसी स्टेन को नहीं, बल्कि जीती और एक्टर के बाद ज्यादा पसंद किया गया है जिससे ऐप की फैन फॉलोइंग काफ़ी घटती दिखी। आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन यही सच है कि एमसी स्टेन की लोकप्रियता

बॉलीवुड

बॉलीवुड